



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2020

भाद्रपद 9, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1565/79-वि-1-20-1(क)-26-20

लखनऊ, 31 अगस्त, 2020

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020 जिससे राज्य कर अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के

लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा;

(2) यह दिनांक 31 मार्च, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 5
सन् 2008 में नई
धारा 29क का
बढ़ाया जाना

2-उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 29 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

“29क-(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, विशेष परिस्थितियों में समय बढ़ाने की सरकार की शक्ति अधिसूचना द्वारा ऐसी कार्यवाहियों, जो अपरिहार्य घटना के कारण पूर्ण नहीं की जा सकती हैं अथवा जिनका अनुपालन नहीं किया जा सकता है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम अथवा तदधीन बनायी गयी नियमावली में विनिर्दिष्ट अथवा विहित अथवा अधिसूचित समय सीमा में वृद्धि कर सकती है।

2-इस धारा की शक्ति में ऐसे दिनांक, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व का न हो, से ऐसी अधिसूचना में भूतलक्षी प्रभाव प्रदान करने की शक्ति सम्मिलित होगी।

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजन के लिए पद ‘अपरिहार्य घटना’ का तात्पर्य युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, अग्नि, चक्रवात, भूकम्प अथवा प्रकृति के कारण या, इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के क्रियान्वयन को अन्यथा रूप में प्रभावित करने वाली किसी अन्य आपदा से है।”

निरसन और
व्यावृत्ति

3-(1) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश संख्या 14
सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन्, 2008) माल के अंतः राज्यीय विक्रय पर कर उद्ग्रहण एवं संग्रहण का उपबन्ध करने के लिये अधिनियमित किया गया है।

2-कोविड-19 के कारण लाक-डॉउन के फलस्वरूप करदाताओं के समक्ष उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को नियंत्रित करने हेतु सरकार को, भूतलक्षी प्रभाव से (अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से अपूर्वतर) ऐसी कार्यवाहियों, जो अपरिहार्य घटना के कारण पूर्ण नहीं की जा सकती हैं अथवा जिनका अनुपालन नहीं किया जा सकता है, के संबंध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट अथवा विहित अथवा तदधीन अधिसूचित समय-सीमा में वृद्धि करने की शक्ति प्रदान करने के लिये, उक्त अधिनियम में एक नई धारा बढ़ाये जाने का विनिश्चय किया गया।

3-चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 06 जुलाई, 2020 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन्, 2020) प्रख्यापित किया गया।

4-यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 1565(2)/LXXIX-V-1-20-1(ka)-26-20

Dated Lucknow, August 31, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mulya Samvardhit Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 28, 2020. The Rajya Kar Anubhag-2, is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2020

(U.P. Act no. 23 OF 2020)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2020; Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 31st March, 2020.

2. After section 29 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, the following section shall be inserted, namely:— Insertion of new section 29A in U.P. Act no. 5 of 2008

"29A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, by notification extend the time limit specified in, or prescribed or notified under, this Act or rules made there under in respect of actions which can not be completed or complied with due to *force majeure*.

Power of Government to Extend time in Special circumstances

(2) The power of this section shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of commencement of this Act.

Explanation-For the purpose of this section the expression *force majeure* means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act."

3. (1) The Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2020. is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 14 of 2020

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Value Added Tax Act (U.P. Act no. 5 of 2008) has been enacted to make a provision for levy and collection of tax on *intra-state* sale of goods by the State of Uttar Pradesh.

2. To overcome the difficulties faced by tax payers, arising by reason of Lockdown due to COVID-19, it had been decided to inset a new Section in the said Act to empower the Government to extend the time limit retrospectively (not earlier than the date of commencement of the Act), specified in or prescribed or notified under this Act in respect of actions which cannot be completed or complied with due to *force majeure*.

3. Since the State legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance no. 14 of 2020) was promulgated by the Governor on July 06, 2020.

4. This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 191 राजपत्र-2020-(564)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 149 सा० विधायी-2020-(565)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।